

## महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के आह्वान पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

### प्रलिमिंस के लिये:

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [राज्यपाल](#), [फ्लोर टेस्ट](#), संविधान की 10वीं अनुसूची, [दल-बदल वरिधी कानून](#), [वहपि](#)

### मेन्स के लिये:

फ्लोर टेस्ट बुलाने की राज्यपाल की शक्ति

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना है कि महाराष्ट्र के पूर्व [राज्यपाल](#) द्वारा सदन में बहुमत साबित करने हेतु तत्कालीन मुख्यमंत्री को [फ्लोर टेस्ट](#) के लिये बुलाने का नरिणय उचित नहीं था। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय पूर्व सरकार को बहाल नहीं कर सकता क्योंकि उसने फ्लोर टेस्ट में भाग नहीं लिया था।

## फ्लोर टेस्ट:

- यह बहुमत के परीक्षण के लिये [इस्तेमाल किया जाने](#) वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है, तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिये कहा जा सकता है।
  - गठबंधन सरकार के मामले में [मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल](#) करने के लिये कहा जा सकता है।
  - [स्पष्ट](#) बहुमत के अभाव में जब सरकार बनाने के लिये एक से अधिक व्यक्तिगत हसिसेदारी की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल यह जानने के लिये एक विशेष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लिये किसके पास बहुमत है।
  - कुछ विधायक अनुपस्थिति हो सकते हैं या मतदान करने से इनकार कर सकते हैं। अर्थात् [आँकड़ों की गणना केवल उन विधायकों के आधार पर की जाती है जो मतदान में उपस्थिति हों](#)।

## पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिरा दिया गया और [उसकी जगह दूसरी सरकार ने ले ली](#), जिसमें शिवसेना का एक गुट शामिल था। शिवसेना से अलग हुए गुट के नेता एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने।
- इसके बाद ठाकरे समूह द्वारा तत्कालीन महाराष्ट्र के [राज्यपाल के इस्तीफे से पहले विश्वास मत](#) के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।

## सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- [फ्लोर टेस्ट पर](#):
  - राजनीतिक दल के भीतर समस्याओं को हल करने के लिये [फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये](#) और पार्टी की असहमत को पार्टी के संविधान या अन्य तरीकों के अनुसार हल किया जाना चाहिये।
- [सचेतक \(Whip\) की नयुक्ति](#):
  - अध्यक्ष को केवल पार्टी संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में [राजनीतिक दल को सचेतक \(Whip\) के रूप में मान्यता देनी चाहिये](#)। सचेतक (Whip) और सदन में दल का नेता दोनों की नयुक्ति केवल राजनीतिक दल द्वारा की जानी चाहिये, न कि विधायक दल द्वारा।
    - संसदीय बोलचाल की भाषा में सचेतक (Whip) सदन में एक पार्टी के सदस्यों को एक नयुक्ति अनुदेशों का पालन करने हेतु एक

लखित आदेश और पार्टी के एक नामित अधिकारी को संदर्भित कर सकता है जो इस तरह के निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है।

◦ सचेतक (Whip) की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से वरिष्ठता में मली थी।

#### ■ दल-बदल के आधार पर अयोग्यता:

- **संवधान की 10वीं अनुसूची** के अनुसार अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर नरिणय लेने का अधिकार है।
- सामान्यतः न्यायालय 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता संबंधित याचिकाओं पर नरिणय नहीं दे सकता है।
  - महाराष्ट्र विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत 40 बागी विधायकों के विरुद्ध नोटिस जारी किये गए थे, जो कि **दल-बदल** के आधार पर अयोग्यता से संबंधित थे।

## संवधान की 10वीं अनुसूची:

- **दलबदल वरिधी कानून:** दसवीं अनुसूची को आमतौर पर 'दलबदल वरिधी कानून' (Anti-Defection Law) के रूप में जाना जाता है। संसद ने इसे वर्ष 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से दसवीं अनुसूची के रूप में संवधान में शामिल किया था।
  - यह दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों (सांसदों) और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की नरिंहता/अयोग्यता से संबंधित प्रावधान करता है।
  - यह नरिवाचति सदस्यों को नरिवाचन के बाद दल परिवर्तन से रोककर राजनीतिक दलों के बीच राजनीतिक स्थिरता और अनुशासन को बढ़ावा देना चाहता है।
- **नरिंहता:** इसके अनुसार, संसद या राज्य विधानमंडल का एक सदस्य तब अयोग्य हो जाता/जाती है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह नरिवाचति हुआ था/हुई थी, अथवा यदि वह राजनीतिक दल के निर्देशों के खिलाफ सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता/रहती है।
  - हालांकि एक सदस्य को अयोग्य नहीं माना जाएगा यदि वह दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के वलिय के कारण दल छोड़ देता/देती है या यदि दल स्वयं किसी अन्य दल में वलिय कर लेता है।
  - 52वें संशोधन के अनुसार, एक राजनीतिक दल के नरिवाचति सदस्यों के एक-तर्हिई सदस्यों द्वारा 'दलबदल' को 'वलिय' माना जाता था।
    - लेकिन 91वें संवधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब किसी पार्टी के कम-से-कम 2/3 सदस्यों को "वलिय" के पक्ष में होना चाहिये ताकि कानून की नज़र में इसकी वैधता हो।
    - 52वें संशोधन के अनुसार, एक राजनीतिक दल के नरिवाचति सदस्यों के एक-तर्हिई को 'दल बदल' को 'वलिय' माना जाता था।
    - लेकिन 91 संवधानिक संशोधन अधिनियम, 2003 ने इसे बदल दिया और अब किसी पार्टी के कम-से-कम 2/3 सदस्य "वलिय" के पक्ष में होने चाहिये ताकि कानून की नज़र में वैध हो।

## फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की राज्यपाल की शक्तियाँ:

#### ■ परिचय:

- **संवधान का अनुच्छेद 174** राज्यपाल को राज्य विधानसभा बुलाने, भंग करने और सत्त्वावसान करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 175(2)** के अनुसार, सरकार के पास संख्या बल है या नहीं यह साबित करने के लिये राज्यपाल सदन को फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है।
  - हालांकि राज्यपाल संवधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार उपरोक्त का प्रयोग कर सकता है जो कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है (जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो)।
  - हालांकि जब सदन सत्र में होता है तो विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट के लिये बुला सकता है।

#### ■ राज्यपाल की वविकाधीन शक्ति:

- **अनुच्छेद 163 (1)** के अनुसार, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों का एक समूह होगा जो राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सहायता और सलाह देगा। हालांकि राज्यपाल का नरिणय किसी भी मामले में अंतिम होगा जहाँ उसे संवधान के अनुसार अपने वविकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक है।
  - संवधान यह स्पष्ट करता है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के वविकाधिकार के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, तो राज्यपाल का नरिणय अंतिम होता है और उसकी किसी भी बात की वैधता पर इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उसे अपने वविकाधिकार से काम करना चाहिये था अथवा नहीं।
- राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत अपनी वविकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जब मुख्यमंत्री ने सदन का समर्थन खो दिया हो और उसकी शक्ति चर्चा योग्य हो।
- वपिकष और राज्यपाल अक्सर तब फ्लोर टेस्ट की एक साथ मांग कर सकते हैं जब उन्हें इस बात का संदेह हो कि मुख्यमंत्री ने बहुमत खो दिया है।

## राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग संबंधी पूर्ववर्ती फैसले:

- **नबाम रेबिया और बमांग फेलकिस बनाम उपाध्यक्ष मामला (2016):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदन को बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में नहित नहीं है और इसका प्रयोग मंत्रपरिषद की सहायता और सलाह से किया जाना चाहिये, न कि स्वयं।

- शविराज सहि चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष (2020): इस प्रकार के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट के लिये बुलाने की स्पीकर की शक्त को बरकरार रखा, यदि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-on-maharashtra-governor-s-call-for-floor-test>

